SHRI N. GIRI PRASAD: A major bottleneck is here. The Central Government, especially the Cantral Water Commission, has to give the techno-economic clearance to this project, and the environmental clearance also has to be given by the Ministry of Environment. Unless these things are done and this project is taken up now to be completed at least by the end of the Ninth Plan, all the States will be affected. So, I request the Government to give top priority to this project in national interest and also in the interest of development of those areas.

Thank you.

Need to enhance post-matric scholarship

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, केन्द्र प्रवर्तित योजना के श्रंतर्गत भारत सरकार द्वारा श्रनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र-छाताओं को पोस्ट मैद्रिक छात्रवृत्ति की राशि एक निर्धारित सीमा के ऊपर राज्य शासन को ग्रनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की विभिन्न दरें दिनांक 1-7-89 से प्रभावित की गई है। इसके बाद से ग्रब तक महंगाई एवं मुद्रास्फीती में निरंतर वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप छात्रवृत्ति की राशि बच्चों के लिए काफी अर्पाप्त होती है। यह इतनी अपर्याप्त है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 8वीं से 10 वीं कक्षा के लिए जो छात्रवृति की दर निर्धारित की गई है, उससे भी कम छात्रवृत्ति 11वीं ग्रौर 12वीं कक्षा के छात्रों को केन्द्रीय शासन द्वारा दी जाती है।

महोदय, जहां एक ग्रोर राज्य शासन की तुलना में केन्द्र शासन द्वारा दी जा रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरें कम हैं, वहीं दूसरी ग्रोर जो छात्रवृत्ति ग्रभी मिल रही है, वह भी ग्राज के मूल्य सूचकांक को देखते हुए बहुत कम है ग्रीर इसमें ग्रनु-सूचित-जाति, ग्रनुसूचित - जनजाति के छात्र- छाताग्रों के लिए पढाई -लिखाई के संसाधन जुटाना किंटिन होता है। केन्द्र प्रवितित योजना

के ग्रंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा दी जा रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दरों को बढाया जाना ग्रावश्यक है, वहीं सिद्धांत रूप से छात्रवृत्ति की दरों को मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध करते हुए प्रति वर्ष जुलाई माह में ग्रैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व तत्समय प्रचलित मूल्य सूचकांक के श्रमुरूप प्रति वर्ष के लिए छात्रवृत्ति की दरों का पुनरीक्षण किया जाना ग्रावश्यक है।

केन्द्र शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के ग्रंतर्गत दी जा रही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता हेतु पाठकों की ग्राय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है ——

- (अ) जिनकी आय पूर्व सधारण भत्ता सीमा रुपए 1500 एवं फीस प्रति माह से अधिक न हो ।
- (ब) जिनकी प्रतिमाह 1. ग्रुप "ए" के ग्राय रुपए 1500 लिए पूण विवरण से ग्रिधिक हो किंतु भत्ता तथा फीस रुपए 2.00 प्रति माह से ग्रिधिक न हो। 2. ग्रन्य ग्रुपों के

. अन्य ग्रुपा क लिए आधार सधारण भत्ता तथा पूर्ण फीस

इक्त विवरण से स्पष्ट है कि रूपए 2,000 प्रति माह से ग्रधिक ग्राय वाले पालको/माता-पिता के बच्चों को केन्द्रीय पोस्ट मैद्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता नहीं है। यह भ्राय सीमा भ्रत्यंत भ्रव्यावहारिक है एवं वर्तमान वेतनमानों के ग्राधार पर यदि किसी परिवार में एक से ग्रधिक व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी की भी सेवा में हैं तो उनके बच्चे केन्द्रीय वेतनमानों की पातता नहीं रखेंगे। कई चतुर्थ श्रेणियों में भी कूल उपलब्धि रुपए 2,000 प्रति माह से ग्रधिक होती है इस ग्राय सीमा को पुनरीक्षित किया जाना भावश्यक है। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने प्रस्ताव भेजा है कि ग्राय सीमा को बढ़ाया जाए ग्रीर उसे मृल्य सूचकांक से जोड़ा जाए।

श्रतः मैं श्रापके माध्यम से माग करता हूं कि केन्द्रीय शासन से जो केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के ग्रंतर्गत ग्रनुसूचित-जाति ग्रौर जनजाति के विद्यार्थियों को जो पोस्ट मैट्रिक छातवृत्ति की राशि दी जाती है, उसकी दरों में वृद्धि की जाए ग्रौर छातवृत्ति का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा जो पालकों की ग्राय सीमा निर्धारित को गई है, उसमें भी वृद्धि की जाए। ग्रापने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए ग्रापका धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Shri Ram Gopal Yadav, absent, Shri Janardan Yadav, absent. Shri Sunder Singh Bhandari, absent. Dr. Murli Manohar Joshi, absent. Shri Satya Prakash Malaviya, absent. Shri Mohd. Masud Khan, absent. Maulana Obaidullah Khan Azmi, absent Dr. Jagannath Mishra, absent. Shri Raghavji, absent. Shri Bhupinder Singh Mann, absent.

Problems faced by Wagon industry

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, the wagon industry in the country is reportedly facing an acute crisis due to lack of orders from the Ministry of Railways. Though there is a budgetary provision for the Ministry to procure 18,000 wagons during the current year, they have not done it. The Ministry of Railways is the sole client for the wagon industry.

According to the "Hindustan Times", dated 2nd May, 1994; even the budge-tary provision for the procurement of 18,000 wagons during the current year is almost 30 per cent less than the plan of 25,000 wagons during the Eighth Plan period. It has been pointed out that it is a labour intensive industry. If the present situation continues for some more time,

then, the wagon industry and most of the ancillary units both in the private sector and the public sector. will be forced to close down their units leading to the throwing out of employment of those who are directly employed and those who are working in the various ancillary units. The Ministry of Railways must take immediate action, without any further delay, to save the industry. Thank you, Sir.

Agitation by diploma Engineers in U.P.

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, करप्शन को वर्ल्ड फिनामिनन मानने वाले अपने देश में ग्रामीण विकास के नाम पर करोड़ों रुपयों की लट पर कोई ग्रचरज न हो तो कोई बडी बात नहीं । लेकिन मैं समझता ह कि ग्राप को इस बात पर जरूर ग्रवरज होगा कि बड़े से बड़े प्रशासनिक ग्रधिकारी ग्रौर शासन, उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार की जानकारी में यह लूट हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक की 10 लाख की योजना के तहत उत्तर प्रदेश को साढे 11 लाख रुपए दिए गए। . . मान्यवर, इस साढे 11 लाख रुपए से कुत्रों का निर्माण होना था. एकीकत सिचाई ग्रौर पेय जल योजना कानिर्माण होनाथा। इसी के साथ साथ ड़ेन का भी निर्माण होना था। कुछ तारीख मैं ग्रापके विचार में लाना चाहता हूं । पहली तारीख है 17 फरवरी, 1993 । 17 फरवरी 1993 को इन कामों के लिए धन श्राबंटित किया गया श्रीर दूसरी तारीख है 16 मार्च, 1993 जिसमें इन बच्चों के प्राक्कलन की स्वीकृति मुख्य श्रधिकारी ने दी श्रौर जो हिदायतें भेजी गई थों उन में से एक हिदायत यह थी कि 31 मार्च, तक इस धन का व्यय जरुर हो जाना चाहिए । निर्माण के लिए कूल 15 दिन का समय दिया था । जाहिर है िक निर्माण हुआ नहीं और मारा का मारा पैसा खर्च कर दिया गया कागजों पर ।...

(उश्तभादित महोदया पीठासीन हुई)

उपसभापति महोदया, मैं प्रर्ज कर रहा था कि साढे 11 लाख रुपया प्रावंटित किया